

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष एम.ए.के. सिंह
सदस्य

निगरानी प्र० क्र० 4104-एक/2013 विस्तृत आदेश दिनांक 03-10-13 पारित
अपर कलेक्टर, सिवनी प्रकरण क्रमांक 59/अ-23/12-13 अपील.

श्रीमती सलमा बेगम पत्नि अब्दुल खालिक खाँ
निजसी ग्राम भोगा, तह० व जिला सिवनी ——— आवेदक
विस्तृत

श. क्र. 170 भोगा उर्फ दादूराम
निजसी ग्राम भोगा, तह० व जिला सिवनी — — — अनादेशक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अध्यापक - आवेदक

आदेश

(आज दिनांक 03/10/2013 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश गू राजस्व अधिनियम 1959 (जिसे आगे
केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, सिवनी के अपील
प्रकरण क्रमांक 59/अ-23/12-13 में पारित आदेश दिनांक 03-10-13 से असन्तुष्ट
होकर प्रस्तुत किया गया है।

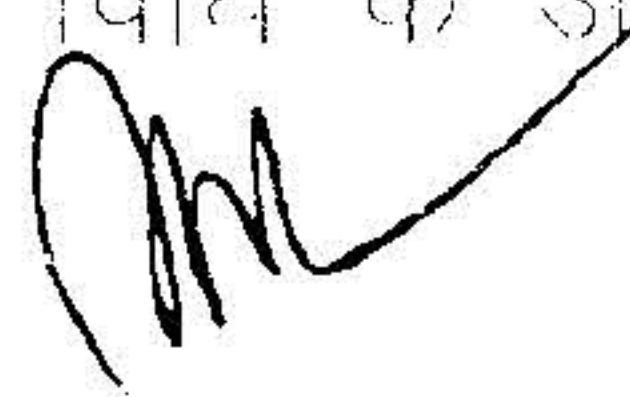
2 प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक राजू भ० भोगा उर्फ दादूराम ने
सिवनी की धारा 170 (आ) के अन्तर्गत राजस्व अनुविभाग अधिकारी के समक्ष
प्रस्तुत किया जिसमें दर्शाया कि नाम भोगा अधिनियम 1959 के तहत पेट्रिक भूमि खसरा नं०
33/2, 33/3 एवं 429/2 कुल रकबा 240 हे० एवं 1085 म० राजू परधान अधिनियम
1959 के तहत भूमि स्वामी रकबा में दर्ज भूमि यह भूमि हलवाई की लिये पहले यह भूमि
राजू भोगा उर्फ दादूराम के नाम दर्ज करवायी और फगोवाई की वसीयत के आधार पर
मुस्त सलमा बेगम का नाम दर्ज करवाया है। अतः उन्होंने भूमि वापिस दिलाये जाने
का अनुरोध किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की

और आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 26-04-2012 में यह निष्कर्ष निकाला कि केता फागू वल्द भोलू गोड के पक्ष में दिनांक 16-04-1984 का विक्रयपत्र छलकपट के आधार पर उषपंजीयत कार्यालय सिवनी में पंजीयत कराया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने पंजीयत विक्रयपत्र को शून्य घोषित कर प्रश्नाधीन भूमि आवेदक राजू वल्द गोमा उर्फ दादूराम जाति परधान के नाम अभिलेख में दर्ज कर कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये।

3. उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक सलमा वेगम द्वारा अपील अपर कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 03-10-2013 में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्नाधीन भूमि राजू आ. गोमा परधान द्वारा आदिवासी केता फागू आ. भोलू गोड को दिनांक 16-04-1984 को विधिवत पंजीयत दरस्तावेज के माध्यम से अन्तरित की गयी। वयनामें 3 साक्षी अयोध्याप्रसाद ने कथनों में प्रश्नाधीन भूमि राजू आदिवासी द्वारा केता फागू आ. भोलू गोड को विधिवत अन्तरित किये जाने और विक्रयपत्र में विक्रेता राजू तथा साक्ष्य में अयोध्याप्रसाद एवं राम सराठे के हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। अतः अपर कलेक्टर ने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का निष्कर्ष वारतविक परीक्षण के अभाव में त्रुटिपूर्ण माना। अपर कलेक्टर ने विक्रेता फागू आ. भोलू गोड द्वारा केता फगोबाई आ. तीजू के पक्ष में दिनांक 8-1-88 एवं 8-2-88 को किये गये अन्तरण को बैनामी होना माना किन्तु अपने आदेश के पैरा 14 में विक्रेता फागू आ. भोलू गोड द्वारा केता फगोबाई आ. तीजू के पक्ष में दिनांक 8-1-88 एवं 8-2-88 को किये गये विक्रयपत्र को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विधिवत विक्रय कर कब्जा प्रदान करने से फागू आ. भोलू गोड को मूल भूमिस्वागी नहीं होना माना। अतः अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन भूमि मूल भूमिस्वागी राजू आ. गोमा उर्फ दादूराम के नाम अंकित कर कब्जा वापस लोटाने के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होना माना और अपील खारिज की। अतः आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।



4. मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक ने लिखित बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक राजू परधान ने फागू आ. भोलू गोड को विक्रय की फागू आ. भोलू गोड द्वारा प्रश्नाधीन भूमि फग्गोबाई आ. तीजू गोड को विक्रय की गयी। दोनों ही पक्ष कर्ता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और संव्यवहार पूर्णतः वैध एवं सदभावी है। फग्गोबाई आदिवासी महिला थी। फग्गोबाई द्वारा पीरबक्स मुसलमान से निकाह किया। फग्गोबाई की कोई सन्तान नहीं थी। आवेदक सलमा बेगम फग्गोबाई की रिश्तेदार है और सलमा बेगम ने फग्गोबाई की सेवा सुश्रुता की जिससे फग्गोबाई ने दिनांक 28-05-1990 को आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत की जिसके आधार पर फग्गोबाई की मृत्यु होने पर राजरव अभिलेख में फग्गोबाई पत्नी पीरबक्स के स्थान पर प्रश्नाधीन भूमि पर नाम दर्ज किया गया है। उनका तर्क है कि अनावेदक राजू परधान ने प्रश्नाधीन भूमि उचित प्राप्फल लेकर फागू बल्द भोलू गोड को विक्रय की है और फागू बल्द भोलू द्वारा प्रश्नाधीन भूमि उचित मूल्य लेकर फग्गो आ0 तीजू गोड को विक्रय की है, इसलिये प्रकरण में संहिता की धारा 165(6) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते। उनका यह भी तर्क है कि सलमा बेगम द्वारा उक्त भूमियों शांताबाई पत्नी रागसिंह, ममताबाई पत्नी प्रहलाद एवं मुस0 रेहाना बी. जौजे मो0 रऊफ का विक्रय की जा चुकी हैं और वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं, किन्तु अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। उनका तर्क है कि फग्गोबाई ने पीरबक्स के साथ निकाह किया था। फग्गोबाई निरसन्तान थी और फग्गोबाई द्वारा आवेदक सलमा बेगम के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है। वसीयतनामा निष्पादित करने हेतु धारा 165(6) की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस संवध में उन्होंने मेरा ध्यान 1994 रा नि. 112 तथा 1999 ए आई आर 1999 जम्मू एण्ड कश्मीर 55 की ओर आकर्षित कर लेख किया है कि वसीयतनामा अन्तरण नहीं है, इसलिये वसीयत करने के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अन्त में उनका तर्क है कि फग्गोबाई न पीरबक्स मुसलमान से निकाह किया था और मुस्लिम विधि के अनुसार फग्गोबाई न मुस्लिम धर्म स्वीकार कर



लिया था। फग्गोबाई की मृत्यु के बाद मुस्लिम विधि के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि फग्गोबाई के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी और फग्गोबाई अपनी सम्पत्ति की वसूली करने हेतु स्वतंत्र थी। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

5. अनवेदक की ओर से तारीख पेशी की सूचना होते हुए भी कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिये उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

6. प्रकरण के तथ्य से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि अनवेदक राजू परधान ने फागू आ. भोलू गोड को पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 16-04-1984 द्वारा विक्रय की। क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही आदिम जनजाति के सदस्य हैं। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि बयानों के साक्षी अयोध्याप्रसाद ने कथनों में प्रश्नाधीन भूमि राजू आदिवासी द्वारा क्रेता फागू आ. भोलू गोड को विधिवत अन्तरित किये जाने और विक्रयपत्र में विक्रेता राजू तथा साक्ष्य में अयोध्याप्रसाद एवं राम सराटे के हस्ताक्षर होने का पुष्टि की है। अतः अपर कलेक्टर ने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का निष्कर्ष वास्तविक परीक्षण के अभाव में त्रुटिपूर्ण होना माना है। फागू आ. भोलू गोड द्वारा प्रश्नाधीन भूमि फग्गोबाई आ. तीजू गोड को दिनांक 8-1-1988 एवं 8-2-88 को पंजीयत विक्रयपत्र द्वारा अन्तरित की गई है। अपर कलेक्टर ने विक्रेता फागू के कथन 4-4-13 को लापेवध किये हैं और अपने आदेश की कण्डिका 14 में यह निष्कर्ष निकाला है कि विक्रेता फागू आ. भोलू गोड द्वारा क्रेता फग्गोबाई आ. तीजू के पक्ष में दिनांक 8-1-88 एवं 8-2-88 को किये गये विक्रयपत्र का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विधिवत विक्रय कर कब्जा प्रदान करने से फागू आ. भोलू गोड को मूल भूमिस्वामी नहीं होना माना जा सकता। इससे स्पष्ट है कि फग्गोबाई आ. तीजू के पक्ष में किये गये अन्तरण को भी कपटपूर्ण या वैनागी होने संबंधी निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं निकाले। मोंगीलाल तथा अन्य पि0 हीरालाल तथा अन्य (1988 रा.नि. 06) में राजस्व मण्डल ने यह व्यवस्था दी है कि



धारा 170-क उपबन्धों का समूह द्वारा आदिम जनजाति के सदस्य द्वारा आदिम जनजाति के पक्ष में अन्तरण- अंतरण बेनामी होना या गैर आदिवासी के पक्ष में होना सिद्ध नहीं- उपबन्ध आकर्षित नहीं होते।

ऐसी दशा में प्रश्नाधीन भूमि का अन्तरण आदिवासी से आदिवासी के पक्ष में होने व अन्तरण बेनामी होना सिद्ध नहीं होने से संहिता की धारा 165(6) एवं 170-क तथा 170-ख के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते।

7. प्रश्नाधीन भूमि फग्गोवाई आ. तीरजू द्वारा पंजीयत विक्रयपत्र द्वारा खरीदी जाने से यह प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी थी। फग्गोवाई द्वारा पीरवक्श मुसलमान से निष्काह करने तथा फग्गोवाई निसन्तान होने के तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है। फग्गोवाई द्वारा आवेदक सलमा बेगम के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 28-5-1990 में निष्पादित किया है। अगर कलेक्टर ने वसीयत के पूर्व धारा 165(6) के अन्तर्गत कलेक्टर की अनुमति नहीं लिये जाने से वसीयत का शून्य माना है। बट्टीप्रसाद वि० समाचार (1994 रा.नि. 112) में राजस्व मण्डल ने यह व्यवस्था दी है कि बिल करने के पूर्व अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। धारा 164 के अधीन भूमिस्वामी को बिल करने का अधिकार है। वेरुराम तथा अन्य वि० शंकरदास तथा अन्य (र आई आर 1999 जम्मू एण्ड कश्मीर 55) में मानग उच्च न्यायालय ने "पसस पे अदज" जतदेमित" होना निर्धारित किया है। इस प्रकरण में मृत फग्गोवाई के वैध उत्तराधिकारी द्वारा वसीयत के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा फग्गोवाई के अन्य किसी वारिस के पक्ष में नामान्तरण के आदेश दिये गये हैं। फग्गोवाई निसन्तान थी, इसलिये उसे अपने स्वत्व की भूमि की वसीयत करने की अधिकारिता संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत थी। ऐसी दशा में फग्गोवाई की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि पर फग्गोवाई पत्नी पीरवक्श के स्थान पर आवेदक सलमा बेगम का नाम दर्ज किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं ली गयी है।



8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 03-10-13 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26-04-12 निरस्त किये जाते हैं। परीयत के आधार पर आवेकक श्रीमती सलमा बेगम का विधवा सहायता नामांतरण स्थापना रखा जाता है।


(हेमेंद्र सिंह)
सदस्य,

राजस्थान मण्डल, म0प्र0
जालियर,